भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 436
उत्तर देने की तारीख 03 फरवरी, 2021

भारतीय मोबाइल कांग्रेस

436. श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे. डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने हाल ही में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कांग्रेस के मुख्य विषय क्या हैं?;
(ग) उक्त कांग्रेस में भाग लेने वाले और मुद्दों पर विचार-विमर्श करने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है;
(घ) विचार-विमर्श किए गए मुद्दों के क्या परिणाम रहे; और
(ङ) क्या भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के साइबर हमले देश में होने वाले कुल साइबर हमलों के 35 प्रतिशत हैं और इसके बाद अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, कनाडा और जर्मनी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) एवं (ख) जी, हां। दूरसंचार विभाग ने भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ (सीओएआई) के साथ दिनांक 8-10 दिसंबर, 2020 तक चतुर्थ वार्षिक भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2020 (एमसी 2020) का आयोजन किया और यह वर्चुअल कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय "समग्र नवाचार-स्मार्ट, सुरक्षित, सतत" था।

(ग) एवं (घ) लगभग सताईस हजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों और प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया इस कार्यक्रम में 170 प्रदर्शक थे जिनमें से लगभग 100 प्रदर्शकों ने स्टार्टअप और लघु, सुक्ष्म एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमइ) उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन किया। आईएमसी 2020 का केंद्र बिंदु 5जी और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, 5जी यूज केस, नेटवर्क ऑटोमेशन, स्मार्ट उपक्रम, क्लाउड/एज परिकलन, इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि थे। आईएमसी ने प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए भारत को विश्व में पसंदीदा देश बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया।

(ङ) समय-समय पर देश के साइबर स्पेस में परिचालित डिजिटल संचार नेटवर्क से जुड़ी प्रणालियों/उपकरणों में अनाधिकृत प्रवेश करने के प्रयास किए गए हैं। ऐसा देखा गया है कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, कनाडा, जर्मनी और अन्य देशों सहित विभिन्न देशों के साइबर स्पेस से इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं।

सरकार अन्य बातों के साथ-साथ नवीनतम साइबर खतरों/अतिसंवेदनशील मुद्दों के संबंध में चेतावनी और परामर्शिकाएं तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए दिशा-निर्देश जारी करती है। आयोजन से पूर्व और नियमित अंतराल पर सभी सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा की जांच की जाती है। साइबर हमलों से निपटने के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है। साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल और सीआईएसओ के नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

******